भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2101

(28 जुलाई, 2014 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कें

2101. श्री रीताब्रता बनर्जी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के कितने प्रतिशत गांवों में पक्की सड़कें हैं; और

(ख) शेष ग्रामीण आबादी को नई सड़कों से जोड़ने हेतु सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा वह इस लक्ष्य को कब तक पाने की इच्छा रखती है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री उपेन्द्र कुशवाहा)

(क) और (ख): "ग्रामीण सड़कें" राज्य का विषय है और बारहमासी सड़कों के माध्यम से मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों (2001 की जनगणना के अनुसार) तथा इससे ऊपर की जनसंख्या वाले कोर नेटवर्क के अनुसार सड़कों से न जुड़ी पात्र बसावटों को जोड़ने के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) भारत सरकार की एक बारगी पहल है। 'विशेष श्रेणी के राज्यों' (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचलप्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तराखंड), मरूभूमि क्षेत्रों, जनजातीय (अनुसूची-v) क्षेत्रों तथा गृह मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा निर्धारित 88 चुनिंदा जनजातीय तथा पिछड़े जिलों में 250 तथा इससे ऊपर (जनगणना-2001) की जनंसख्या वाले कोर नेटवर्क के अनुसार सड़कों से न जुड़ी पात्र बसावटों को जोड़ने का उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पात्र संपर्क विहीन बसावटों को एकल बारहमासी सड़क से जोड़ने की परिकल्पना की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 1,44,547 सड़क संपर्क विहीन पात्र बसावटों को सड़क संपर्कता उपलब्ध कराने हेतु बारहमासी सड़कों के निर्माण के लिए राज्यों के प्रस्ताव परियोजना को मंजूरी दी है। राज्यों ने जानकारी दी है कि उन्होंने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत योजना की शुरूआत से लेकर मई, 2014 तक 2,52,657 कि.मी. सड़कों का निर्माण करके 99,035 सड़क संपर्क विहीन पात्र बसावटों को सड़क संपर्कता उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने 1,96,145 कि.मी. सड़कों के उन्नयन के लिए परियोजना की मंजूरी दी है। राज्यों ने यह भी जानकारी दी है कि उन्होंने मई, 2014 तक 1,51,872 कि.मी. सड़कों का उन्नयन किया है।

*****